(iv) Trained elephants are mostly used for showing wildlife to the tourists inside the park area.

(v) Tourists are advised not to throw garbage in Ramganga river. They are advised to carry back with them, the non bio-degradable litter from the park area.

Consumption of forest wood by Ballarpur Paper Industries

2447. SHRI G. PRATHAPA REDDY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) how much forest wood from the forests of Maharashtra and bordering Andhra has been consumed by the Ballarpur Paper Industries in Chandrapur and the adjoining areas;

(b) at what rate is the wood being supplied to them for the last three years;

(c) on what consideration the wood is supplied to them at a cheap rate; and

(d) whether Government would reconsider its policy in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) As per the reports received from State Forest Departments of Maharashtra and Andhra Pradesh, no forest wood is being supplied to the Ballarpur Paper Industries from the forests of Maharashtra and bordering Andhra Pradesh from the supply year 1991-92 onwards. However, Government of Maharashtra had agreed to make supply of mixed hard-wood to Ballarpur Paper Industries upto the extent of 60,000 Metric Tonnes per year for a period of 20 years from 1971 to 1991 to help the Mills to meet their increasing demands of raw material. The said quantity was later amended to 36,000 Metric Tonnes per year with effect from 14th April, 1978.

(b) to (d) Do not arise.

उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानदण्डों का पालन न किया जाना

2448. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु और बड़े उद्योग प्रदूषण नियंत्रण संबंधी विनियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार की उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी और आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई है; और

(च) क्या मध्य प्रदेश में रायपुर के निकट "केड़िया डिस्टेलरी" तथा शहडोल के निकट "ओरियन्ट पेपर मिल्स" के विरुद्ध अनेकानेक शिकायतें मिलने के बावजूद उनके द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करना बरकरार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) बड़े और मझौले उद्योगों की 17 श्रेणियों के तहत 1551 यूनिटों की शिनाख्त की गई है, जिनमें से 1125 यूनिटों के निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुपालन के लिए पर्याप्त सुविधाएं लगा ली हैं। तथापि, बड़ी संख्या में छोटी यूनिटें वित्तीय अभावों, प्रदूषण नियंत्रण के लिए तकनीकी ज्ञान की कमी और कुछ मामलों में प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्थान की कमी के कारण उत्सर्जन और बहिस्रावों के निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं कर पा रही है।

(ख) सरकार ने छोटी यूनिटों में सस्वच्छ प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट के पुनर्प्रयोग और पुनश्चक्रण की पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए उपाय शुरू कर दिये हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों में अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए क्षेत्र विशिष्ट मैनुअल तैयार करने के वास्ते पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को एक परियोजना प्रायोजित की गई है। छोटे पैमाने के उद्योगों में अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। सरकार द्वारा "छोटे पैमाने के उद्योगों के समूहों में अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल्स स्थापित और संचालित

करने" की एक परियोजना प्रायोजित की गई है। लघु उद्योग विकास संगठन के कार्मिकों के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण में एक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है जिनमें देश भर में छोटे पैमाने के उद्योगों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) और (घ) सरकार के पास छोटे पैमाने के उदयोगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने की एक स्कीम है। यह स्कीम स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाए जाने एवं उसके प्रसार को विकास और अनुसंधान के साथ जोड़ती है तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में जागरूकता कार्यक्रम और कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

इसके अलावा, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत छोटे पैमाने की यूनिटों में सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र और औद्योगिक अपशिष्ट जल पुनश्चक्रण संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने की एक स्कीम सरकार के पास है। इस स्कीम के तहत 50% अथवा 1 करोड़ रुपए की राशि जो भी कम हो, राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, 30% परियोजना लागत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के जरिए उदार ऋण के रूप में प्रदान की जाती है तथा शेष 20% राशि प्रोत्साहक के अंशदान के रूप में दी जाती है। अपशिष्ट पुनः प्रयोग, अपशिष्ट न्यूनीकरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदर्शन और प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना करने के लिए मझौले और बड़े उद्योगों को भी सहायता दी जाती है।

(ङ) सरकार ने छोटे पैमाने की औद्योगिक यूनिटों के समूहों के लिए सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के वास्ते राज्य सरकारों को लगभग 11.00 करोड़ रुपए की राशि बंटित की है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

(च) मैसर्स ओरिएण्ट पेपर मिल्स निर्धारित मानकों के अनुसार बहिस्रावों का उत्सर्जन कर रहा है। तथापि, बहिस्रावों में रंग की समस्या मौजूद है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहडोल की अदालत में इस उद्योग के खिलाफ एक मामला दायर किया है। यह मामला इस समय न्यायालय में लंबित है। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (क) के अंतर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है।

मैसर्स कैड़िया डिस्टीलरी के संबंध में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33, 43,44 और 47 के अंतर्गत उद्योग के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग की अदालत में एक मामला दायर किया है। बोर्ड ने उद्योग को यह भी निदेश दिया है कि वह द्वितीयक और तृतीयक शोधन सुविधाओं की स्थापना के लिए तत्काल कार्रवाई करे।

Poaching of Wildlife in Darjeeling

2449. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the poaching of valuable wild lives in the forests of Darjeeling hills which has threatened the existence of rare species in this part of Himalayan region;

(b) if so, how many raids were conducted by the Department and the police to apprehend the culprits during the last three years; year-wise;

(c) what were the details of recovered materials with approximate value in term of rupees; and

(d) how many poachers were arrested with details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) According to the information furnished by the State Forest Department poaching of wildlife is a problem in the forests of Darjeeling hills.

(b) to (d) The details are given below: